गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 218
दि. 09.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

‘500 करोड़ में सीएम बनता है’-नवजोत कौर के बयान से मचा भूचाल, कांग्रेस ने तत्काल सदस्यता निलंबित की

(जीएनएस)। देश की राजनीति में एक बार फिर चिंगारी भड़क उठी है, और इस बार केंद्र में हैं पंजाब के पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू। उनके बयान ने ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मामला शुरू हुआ एक ऐसे बयान से, जिसने न केवल विपक्ष को हमला करने का मौका दिया, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी बड़े सवाल उठा दिए। नवजोत कौर ने दावा किया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसके पास 500 करोड़ रुपये का ‘सूटकेस’ देने की ताकत हो। उनके इस बयान ने जैसे ही हवा पकड़ी, सियासी दुनिया में मानो आग लग गई।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में नवजोत कौर ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि पंजाबियत का नारा लगाने वाले लोग आज इतने मजबूर हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए करोड़ों का अमीर होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वे या उनका परिवार इस दौड़ में कभी शामिल नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी ने उनसे प्रत्यक्ष रूप से पैसे नहीं मांगे, परंतु “सूटकेस संस्कृति” अब राज्य की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है—यह टिप्पणी जैसे ही बाहर आई विपक्ष को कांग्रेस पर हमला बोलने का सुनहरा मौका मिला। बयान ने राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मचा दी। कांग्रेस ने कुछ घंटों के भीतर ही कठोर कदम उठाते हुए नवजोत कौर को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पार्टी का कहना है कि जिस समय वह संगठन को एकजुट करने में लगी है, ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान उसकी छवि को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन विवाद यहीं नहीं खत्म हुआ। नवजोत कौर ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए दावा किया कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कांग्रेस ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा और न ही उन्होंने किसी पर सीधा आरोप लगाया। उनका कहना है कि बात सिर्फ उस सवाल की थी,

जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या सिद्धू किसी दूसरी पार्टी में जाकर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। उन्होंने अपनी बात यह कहकर खत्म की कि उनके पास ऐसे पदों के लिए देने को कोई धन नहीं है। लेकिन सफाई देने के बावजूद नुकसान हो चुका था। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने इस बयान को हाथों-हाथ लिया और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस के आंतरिक सिस्टम का “घिनौना सच” है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह बयान साबित करता है कि कांग्रेस में टिकट और पद पैसे के आधार पर तय होते हैं। आप नेताओं ने सिद्धू परिवार की टिप्पणी को पुरानी कांग्रेस संस्कृति का नमूना बताते हुए कहा कि इस पार्टी में ईमानदार लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल मीडिया पर भी यह बयान मुद्दा बन गया और कांग्रेस की आलोचना तेज हो गई।

इसी बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी विवाद में कूद पड़े और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पुराने दिनों का किस्सा जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब उनके दादा मुख्यमंत्री थे, तब पार्टी में ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बिट्टू ने दावा किया कि कांग्रेस के अंदरूनी सिस्टम में जांच की कोई परंपरा नहीं है। उनका आरोप था कि पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तक अजीबोगरीब मांगें पहुंचती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मज़ाक में कहा था कि पैसे की जगह गांधी परिवार को मोज़े और अंडरवियर भेजे जाते थे, और दिल्ली से सूची आती थी कि कौन-कौन सा सामान भेजना है। बिट्टू के इस बयान ने विवाद में और आग लगा दी, क्योंकि इसने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के भीतर कई नेता निजी तौर पर मानते हैं कि इस विवाद ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, ठीक ऐसे समय में जब वह पंजाब में अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सिद्धू पहले ही पार्टी से अंदरूनी मतभेदों के कारण चर्चाओं में रहे हैं, और अब उनकी पत्नी का यह विवाद सार्वजनिक रूप में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के लिए यह घटना सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं, बल्कि उस अंदरूनी खींचतान का संकेत है जो लंबे समय से पंजाब कांग्रेस की सियासत को जकड़े हुए है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मामले को यहीं खत्म समझेगी या आगे कोई जांच या अनुशासनात्मक कदम उठाएगी। फिलहाल इतना तय है कि नवजोत कौर सिद्धू का यह एक बयान पंजाब की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर चुका है और आने वाले दिनों में इसके कई और राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं।

बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद: गिरिराज सिंह ने बताया राजनीतिक चाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में हाल ही में उठे ‘बाबरी मस्जिद’ विवाद को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला किसी एक निलंबित विधायक के व्यक्तिगत कदम का परिणाम नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी जानबूझकर हिंदू–मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर राज्य में तनाव पैदा कर रही हैं। उनके अनुसार यह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके राजनीतिक प्रभाव पूरे देश में महसूस किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाना एक व्यक्तिगत कदम नहीं था। यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री की राजनीतिक चाल का हिस्सा है, जिसका मकसद राज्य में संवेदनशील सामाजिक मुद्दों का फायदा उठाना है। गिरिराज सिंह ने चेतावनी दी कि ऐसे विवादों के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने वाले लोग जनता की आंखों में पकड़ में आ जाएंगे और उनकी सियासी चाल का जवाब मिलने में देर नहीं लगेगी।

गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर ‘वंदे मातरम’ को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह गीत केवल एक राष्ट्रगान नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत और भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग ‘वंदे मातरम’ की महत्ता को नजरअंदाज कर केवल विवादास्पद मुद्दों जैसे ‘बाबरी मस्जिद’ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका कहना था कि संसद जैसे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर इस गीत का सम्मान और इसके महत्व पर खुलकर चर्चा होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि ‘वंदे मातरम’ राष्ट्र को एकजुट करने वाला प्रतीक है, और इसे राजनीतिक मतभेदों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगी रहेगी, ऐसे विवादों के माध्यम से समाज में तनाव फैलाना आसान नहीं होगा। उन्होंने मीडिया और जनता को चेताया कि राज्य और देश में संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने वाले लोग जनता की समझदारी और लोकतांत्रिक चेतना से नहीं बच पाएंगे। इस बयान के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने बंगाल में उभरे विवाद को न केवल राजनीतिक दृष्टि से गंभीर बताया बल्कि इसे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने पर भी असर डालने वाला बताया। उन्होंने जोर दिया कि राजनीतिक चालों को किसी भी हालत में राष्ट्र और समाज की प्राथमिकताओं से ऊपर नहीं रखा जा सकता और लोकतंत्र में संवेदनशील मुद्दों को संभालने की जिम्मेदारी सरकार और नेताओं पर ही है।

बंधकों के अवशेषों पर अटका संघर्ष विराम का अगला दौर गाज़ा के भविष्य को लेकर इज़राइल-हमास खींचतान और तेज

(जीएनएस)। इज़राइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम प्रक्रिया एक बार फिर उस बिंदु पर अटक गई है, जहाँ दोनों पक्ष एक-दूसरे पर देरी और दबाव की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि संघर्ष विराम का दूसरा चरण तभी शुरू होगा जब हमास गाज़ा में मौजूद अंतिम इज़राइली बंधक के अवशेष सौंप देगा। जर्मन चांसलर फ्रेड्रिक मर्ज के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि यह शर्त सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि दूसरे चरण का आधार है, क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इसी प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण कदम पर निर्भर करती है।

इज़राइल के अनुसार हमास के पास अभी भी रान ग्विली नामक 24 वर्षीय पुलिसकर्मी के अवशेष मौजूद हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में मारे गए थे। ग्विली के अवशेषों की वापसी की एवज में इज़राइल 15 फिलिस्तीनी शव लौटाने की तैयारी में है, और इसे संघर्ष विराम के पहले चरण का अंतिम पड़ाव माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि जब तक यह आदान-प्रदान पूरा नहीं होता, आगे बढ़ना संभव नहीं है। दूसरी तरफ हमास का दावा है कि दो वर्षों से जारी सैन्य कार्रवाई

के बाद गाज़ा के मलबे में दफ़न शवों को ढूँढना बेहद मुश्किल है, और कई इलाकों तक पहुँचना अब भी जोखिम भरा है। हमास का यह भी कहना है कि इज़राइली सेना द्वारा बमबारी किए गए क्षेत्रों में सुरंगों का ढांचा नष्ट हो चुका है, जिससे खोज अभियान सुस्त गति से चल रहा है। लेकिन इज़राइल इसे टालमटोल की रणनीति बता रहा है और चेतावनी दे चुका है कि अगर अवशेष समय पर नहीं लौटाए गए, तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है अथवा मानवीय राहत सामग्री सीमित की जा सकती है।

इस मुद्दे पर बंधक परिवारों के प्रतिनिधि समूह ने भी सरकार की लाइन पकड़ ली है। उन्होंने कहा है कि जब तक ग्विली के अवशेष वापस नहीं आते, तब तक दूसरा चरण शुरू करना न केवल अनुचित होगा बल्कि उनके लिए भावनात्मक रूप से अस्वीकार्य भी है। उनका यह भी कहना है कि किसी भी समझौते में बंधकों या उनके अवशेषों से जुड़े मामलों पर एक-स्पष्ट और कठोर नीति होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो।

दूसरा चरण जहाँ अटका है, वहीं तीसरे पक्ष की भूमिका लगातार बढ़ रही है। गाज़ा में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और अस्थायी फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना का प्रस्ताव अमेरिका के नेतृत्व में तैयार किए गए फ्रेमवर्क के केंद्र में है। इस ढांचे की निगरानी एक वैश्विक बोर्ड करेगा जिसमें कई पश्चिमी और खाड़ी देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेतन्याहू का कहना है कि यह मॉडल जटिल और चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन असंभव नहीं—क्योंकि इसी तरह की व्यवस्था जापान, जर्मनी और कुछ खाड़ी देशों में सफल रही थी। इज़राइल का दावा है कि गाज़ा को उग्रवाद-मुक्त करने का अंतिम लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमास को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसकी सैन्य, वित्तीय तथा सुरंग संरचना को समाप्त कर दिया जाएगा।

जर्मन चांसलर भी प्रेस वार्ता में इस प्रयास के समर्थन में दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि गाज़ा से जुड़े संचालन में मदद के लिए जर्मनी ने अपने अधिकारियों को दक्षिणी इज़राइल स्थित अमेरिकी समन्वय केंद्र में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही जर्मनी द्वारा मानवीय सहायता भेजने की प्रक्रिया भी जारी है, ताकि संघर्ष विराम के दौरान नागरिकों को राहत मिल सके। मर्ज ने यह स्पष्ट किया कि गाज़ा के पुनर्निर्माण में कोई भी कदम तभी संभव है जब दूसरे चरण को अमल में लाने पर दोनों पक्ष सहमति दें। इज़राइल-हमास समझौते का दूसरा चरण जितनी बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती है, उतनी ही मानवीय दृष्टि से संवेदनशील भी। इस चरण की शुरुआत से पहले जिस “एक अवशेष” की प्रतीक्षा की जा रही है, वह अब सिर्फ युद्धकालीन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की चाबी बन चुका है। जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, तनाव भी बढ़ता दिख रहा है—और विश्व समुदाय की निगाहें अब इसी बात पर टिक गई हैं कि यह अवशेष कब लौटता है और संघर्ष विराम आगे किस दिशा में बढ़ता है।

मणिपुर में उग्रवाद पर बड़ी कार्रवाई: चार हथियारबंद उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त

(जीएनएस)। इंफाल। मणिपुर पुलिस और राज्य के सुरक्षा बलों ने रविवार को एक बार फिर उग्रवादी नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए चार हथियारबंद उग्रवादियों को अलग-अलग अभियानों में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी राज्य में चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उग्रवादी गतिविधियों को रोकना, अवैध वसूली और अपराध पर लगाम लगाना है। गिरफ्तारियां विष्णुपुर, इंफाल पूर्व और लमसांग क्षेत्रों में हुईं और इनके साथ भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण बरामद किए गए। पहली गिरफ्तारी विष्णुपुर जिले के नाइखोंग खुलेन अवांग लाइकै में हुई। यहां प्रीपाक का सक्रिय सदस्य लमाबम रोशन सिंह उर्फ केथम (24) को उसके घर से पकड़ा गया। तलाशी के दौरान दो स्टैलियन प्रो गन, 12-बोर के 13 जिंदा कारतूस, एक नंबर-36 हैंड ग्रेनेड, दो वॉकी-टॉकी सेट, चार्जर, बीपी जैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रोशन सिंह ने हाल के महीनों में कई उग्रवादी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उसका नेटवर्क राज्य में भय और असुरक्षा फैला रहा था।

इंफाल पूर्व के लामलाई इलाके में सुरक्षा बलों ने केवाईकेएल के कैडर लोंगजाम मोचा मैतेई उर्फ राज (41) को उनके निवास से गिरफ्तार किया। मोचा मैतेई लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों और असामाजिक कृत्यों में लिप्त था। लमसांग थाना क्षेत्र से यूएनएलएफ (के) से जुड़े युमखैबम ब्रोजेन सिंह (50) को भी गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पता चला कि ब्रोजेन सिंह रंगदारी वसूली और अन्य अपराधों में सक्रिय था। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन, आधार कार्ड और एयरटेल एयरफाइबर उपकरण बरामद किए गए, जो उसके अवैध नेटवर्क के संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे थे। अधिकारियों ने तीसरी गिरफ्तारी विष्णुपुर जिले के निंगथौखोंग मथक लाइकै में की। यहां केसीपी (नौंगद्रेनखोम्बा) गुट के सदस्य हाओबिजाम निंगतंबा मैतेई (31) को पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि हाओबिजाम का नेटवर्क राज्य में उग्रवाद को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों पर दबाव बनाने के लिए सक्रिय था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान राज्य में उग्रवादी गतिविधियों और अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ जारी है और उनसे उग्रवादी गुटों के अन्य सक्रिय सदस्यों और उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन अभियानों से मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

राज्य पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को दें, ताकि राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। सुरक्षा बलों का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और उग्रवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

इंडिगो उड़ान संकट पर सुप्रीम कोर्ट का रुख : सरकार पर छोड़ी जिम्मेदारी, त्वरित सुनवाई से इनकार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन में आई अचानक भारी बाधाओं ने पिछले कुछ दिनों में हवाई यात्रा को लगभग संकट की स्थिति में ला दिया है। उड़ानें एक के बाद एक रद्द होने लगीं, एयरपोर्ट पर हजारों यात्री घंटों लाईनों में खड़े रहे, टिकट काउंटरों और गेटों पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। इसी अव्यवस्था और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और स्थिति को “राष्ट्रीय महत्व का आपदा-स्तर मुद्दा” बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। लेकिन शनिवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए साफ कहा कि सरकार पहले से इस मामले पर सक्रिय है और फिलहाल न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा मेंशन करते हुए याचिकाकर्ता ने दलील दी कि महामारी के बाद घरेलू उड्डयन क्षेत्र पहले ही दबाव में है और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइन द्वारा दिन भर की दर्जनों उड़ानें रद्द किए जाने से न सिर्फ यात्रियों को असुविधा हुई है, बल्कि हजारों व्यापारिक, चिकित्सा और पारिवारिक यात्राएं ठप हो गई हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की कि वह केंद्र सरकार और डीजीसीए को तत्काल निर्देश दे कि वे एयरलाइनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करें, रद्द उड़ानों की वास्तविक वजहें सार्वजनिक करें और प्रभावित यात्रियों के मुआवजे को लेकर एक स्पष्ट नीति लागू कराएं।

लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत तब हस्तक्षेप करती है जब किसी मामले में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह असफल हो जाए या कोई मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा हो। उन्होंने कहा कि इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं का संज्ञान केंद्र सरकार ने पहले ही ले लिया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइन के संचालन से जुड़े तकनीकी और स्टाफिंग दोनों मुद्दों की समीक्षा कर रहा है। सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि “सरकार स्थिति संभालने की प्रक्रिया में है, ऐसे में कोर्ट अभी कोई त्वरित आदेश जारी नहीं करेगा।”

उधर एयरलाइन सूत्रों का कहना है कि हालिया व्यवधानों की मुख्य वजह ग्राउंड स्टाफ और तकनीकी टीम में अचानक आई कमी, मेंटेनेंस शेड्यूल में गड़बड़ी और मौसम से जुड़ी रुकावटें हैं, जिनके चलते कई रूट प्रभावित हुए। हालांकि यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन ने उन्हें समय रहते सूचना नहीं दी, न ही वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की, जिससे कई यात्रियों की रातें एयरपोर्ट की बेंचों पर ही कट गईं। सोशल मीडिया पर भी यात्रियों के आक्रोश से भरे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

सरकार ने एयरलाइन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वह उड़ानों के लगातार रद्द होने और यात्रियों की शिकायतों पर तथ्यात्मक जांच करे। सूत्रों के अनुसार यदि इंडिगो की ओर से परिचालन संबंधी चूक या उपेक्षा पाई गई तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार यह भी विचार कर रही है कि भविष्य में किसी भी एयरलाइन द्वारा अचानक बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने की स्थिति में तत्काल राहत-योजना कैसे लागू की जाए, ताकि यात्रियों को बेवजह की दिक्कत न झेलनी पड़े।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख ने यह संकेत दे दिया है कि यह मामला न्यायालय के लिए अभी “अत्यावश्यक हस्तक्षेप” की श्रेणी में नहीं आता और समाधान का प्राथमिक दायित्व सरकार और नियामक संस्थाओं के पास ही है। यात्री इंतज़ार में हैं कि देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन जल्द से जल्द सामान्य संचालन में लौटे और हाल की अव्यवस्थाओं की पुनरावृत्ति न हो।

संपादकीय

जेल में पाठशाला

वस्तुतः जेल की मूल अवधारण, भटके लोगों को सभ्य समाज के अनुरूप ढालने की ही थी। यही मकसद था कि जेल के एकाकी जीवन में रहकर वे समाज के महत्व को समझ सकें और अपने गलतियों पर आत्ममंथन करें। संगीन अपराधों में लिप्त दुर्दांत अपराधियों को समाज से अलग रखने की तार्किकता हो सकती है। सुधार की अवधारण के क्रम में अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की जेलों में खामोशी से बदलाव की सकारात्मक पहल की जा रही है। जेलों में ग्यारह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई की शुरूआत की गई है। यह पहल राष्ट्रीय कौशल विकास मानकों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम एनसीवीईटी व एनएसक्यूएफ प्रमाणन के तहत की जा रही है। जिसे कैदियों के जीवन में बड़े बदलाव के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। इसके अंतर्गत ढाई हजार से ज्यादा कैदियों को वेल्डिंग, प्लंबिंग व टेलरिंग आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाना है। निश्चय ही इसे देश की जेलों में महत्वाकांक्षी सुधारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, इस पहल के मूल में यह सोच है कि अपराध में कमी कठोर कारावास से नहीं बल्कि जेल की चाहरदिवारी से बाहर निकलने पर जीवन नये सिरे संवारने लायक बनाने में सहायक आवश्यक साधन प्रदान करने से संभव होगी। कौशल विकास, परामर्श, व्यावहरिक प्रशिक्षण और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों या एमएसएमई योजनाओं के साथ कैदियों को रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। इसे एक सुरक्षित सामाजिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है।

निश्चित रूप से यदि कोई कैदी प्रमाणित कौशल, सम्मानजनक पेश की संभावना और बदलावकारी भावना के साथ जेल से बाहर आता है, तो उसके फिर से अपराध करने की संभावना उस व्यक्ति के मुकाबले कम होगी, जो असुरक्षित भविष्य व रोजगार के अभाव में फिर से अपराध की गलियों की तरफ मुड़ सकता है। इस सोच को जमीनी रूप से हकीकत में बदलने के लिए उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना होगा, जिनका सामना जेल से बाहर आने पर कैदियों को करना पड़ता है। इसमें जेल से बाहर आने पर कैदियों को अपराध के दाग के रूप में भेदभाव का शिकार होने, उन्हें नियोक्ता द्वारा रोजगार देने में हिचकिचाहट दिखाने, अपर्याप्त नौकरियां जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। निश्चय ही उनके पुनर्वास के लिये व्यावहारिक प्रयासों की जरूरत होगी। इसके साथ ही उद्योग प्रबंधकों को रिहा हुए कैदियों को नौकरी देने के लिये प्रोत्साहित करना होगा। यह बताते हुए कि यह हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है। समाज को भी उनके पुनर्वास को एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकारने के लिये संवेदनशील बनाया जाना होगा। निश्चित रूप से हरियाणा व पंजाब नीतिगत दोरोहे पर खड़े हैं। अब देखना है कि वे इस पहल को एक प्रतीकात्मक सुधार के रूप में देखते हैं या वे इसे एक संरचनात्मक परिवर्तन में बदल सकने में कामयाब होते हैं। यदि ऐसा होता है तो वे न्याय को ही पुनर्परिभाषित करेंगे। निस्संदेह, सच्चा सुधारात्मक न्याय कारावास में नहीं, बल्कि भटके हुए नागरिकों को सम्मान, अवसर और आशा के साथ वापस समाज में लाने में निहित है।

रूसी हाथ मगर बहुध्रुवीय व्यवस्था के भी साथ

> ऐसा लगा कि अब भारत अपना वजूद दर्शा रहा है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का स्वागत एक पुराने दोस्त की भांति किया, लेकिन नज़र परिदृश्य में मौजूद दूसरे दोस्तों पर भी उतनी रखी। बहुध्रुवीय या गुट-निरपेक्षता का संदेश साफ़ है।

जब उठी चर्चा- कयासों की सारी धूल बैठ जाएगी और घोषणाओं का शंखनाद हो चुका होगा और गले मिलना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, तब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई शिखर वार्ता में एक छोटी सी यादगार इस मिलन का प्रतीक बन जाएगी -- वह फोटो, जिसमें मोदी, पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भगवद गीता की एक प्रति भेंट कर रहे हैं।

आप पूछेंगे, तो क्या हुआ। लेकिन जरा गौर से देखिए। किताब लेते समय जहां रूसी राष्ट्रपति मुस्कुरा रहे हैं, कुछ-कुछ अर्ध-असमंजस अंदाज़ में, वहीं प्रधानमंत्री की नजर कहीं अधिक संयमित है और उसमें कई छिपे हुए संदेश हैं – गीता की सदियों पुरानी सभ्यतागत शिक्षाएं; कुरुक्षेत्र की रणभूमि से न्याय की खातिर लड़ी जाने वाली लड़ाई का संदेश; तीन साल से यूक्रेन में युद्धरत पुतिन की मंशा पर परोक्ष टिप्पणी; और पश्चिम हेतु संदेश, जो उत्सुकता से भारत को लाल कालीन बिछाकर उस आदमी का स्वागत करते देख रही है, जिस पर कड़ी पाबंदियां ठोक रही है, कि भारत शांति के पाले में है, न कि यूक्रेन संघर्ष में महज एक तटस्थ पक्ष।

काफी अर्से बाद, गत सप्ताह ऐसा लगा कि भारत ने अपना वजूद दर्शाया है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप द्वारा दी जाने वाली चोटों के परिप्रेक्ष्य में (व्यापार संबंधित, अमेरिकी राष्ट्रपति का ज़ोर-शोर से प्रचार करना कि ऑपरेशन सिंदूर को रूकवाने में उन्होंने मध्यस्था की थी, और व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर का रेड कार्पेट वेलकम),मोदी ने अवश्य तय कर लिया होगा कि अब बहुत हुआ और वक्त है अपने अस्तित्व का अहसास कराने का। पुतिन का भारत आना काफी समय से लंबित था –पिछली बार वे चार साल पहले आए थे।

मोदी ने उनका स्वागत गर्मजोशी से करने का फैसला सिर्फ़ इसलिए नहीं किया कि ट्रंप मुनीर के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, या इसलिए नहीं कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है, या इसलिए नहीं कि भारत-रूस के बीच 64 बिलियन डॉलर मूल्य के आपसी द्विपक्षीय व्यापार में भारत का अकेले ऊर्जा संबंधी आयात 55 बिलियन डॉलर है–बल्कि भू-राजनीति के बुनियादी सबक : 'न तो कोई दोस्त स्थाई होता है न ही दुश्मन, स्थाई कुछ है, तो केवल स्वः हित'।

यूक्रेन संकट का बेहतरीन उदाहरण देखें। अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है – जिसमें भारत को ऊर्जा आपूर्ति करने वाली चार रूसी कंपनियां भी शामिल हैं – हालांकि ट्रंप व सहयोगी भी युद्ध रुकवाने को बार-बार पुतिन से मिले हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति अपनी रूख पर अडिग हैं; पिछले तीन सालों उन्होंने न सिर्फ़ यूक्रेनियन लोगों से – बल्कि यूक्रेनियनों के मददगार यूरोपियन एवं अमेरिकियों से भी – डोनबास जैसे रूसी भाषी इलाकों पर कब्ज़ा करने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने में गुजारे हैं। यह भू-राजनीति का दूसरा सबक है कि ताकतवर विरोधियों का सामना मुमकिन है, जब तक आपके पास ऐसा करने की ताकत हो। मोदी जानते हैं कि बड़ी ताकतों – चीनी, अमेरिकियों और रूसियों – में यह अस्वाभाविक काबलियत है कि जब उन्हें अपनी चलानी हो तो वे उच्च नैतिक मूल्यों को तज देते हैं। उन्हें अहसास है कि भारत को उनसे सबक लेते हुए खुद एक आर्थिक ताकत बनाना होगा। लेकिन यह कैसे हो पाएगा, जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है।

समस्या है कि भारत काफी हद तक अमेरिकी बाजार पर निर्भर है, इसीलिए एक सहानुभूतियुक्त व्यापार समझौते की ज़रूरत है;निर्भरता चीनी मार्केट पर भी है, जो दुनिया के अन्य देशों से कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान बेचता है, इसकी वजह से 100 बिलियन डॉलर के द्वि-पक्षीय व्यापार में चीन का पलड़ा बहुत भारी है;और हमारी निर्भरता सस्ती ऊर्जा जरूरतों हेतु रूसी बाजार पर भी है, जो भारतीय आर्थिकी को संबल हेतु अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले कियाफती रखने में मददगार है। तो फिर, क्यों न सभी पक्षों से संवाद रखा जाए और हरेक के साथ अर्थपूर्ण रिश्ते बनाए जाएं।

इसीलिए बीते शुक्रवार को जब पुतिन का जहाज दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, तो मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन की अगवानी की। दोनों नेताओं ने स्वागत कार्यक्रम में एक सांस्कृति आयोजन का आनंद लिया और फिर रात्रि भोज के लिए रवाना हुए। खास बात यह है कि किसी समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए, सिर्फ सहमति पर समझ बनी है -- यह बात घबराए पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए राहत भरी रही, खासकर यूरोपियन यूनियन के उन मुल्कों के लिए जिनके नेता अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोहों में मुख्य अतिथि बनने जा रहा हैं। यह कि भारत रूसी गठबंधन के आगे नहीं झुकेगा, भले ही उसे सस्ते रूसी तेल की सख्त जरूरत है।

इसलिए कोई हिंदी-रूसी भाई-भाई वाली नारेबाजी नहीं हुई -- यह काफी कुछ अतीत के पुराने दिनों,अच्छे थे या बुरे, जैसा लगा, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप किस की तरफ हैं। इसकी बजाय, रणनीतिक बदलावों के बारे में बहुत बयानबाजी हो रही हैं, कि यह किसी अन्य से रिश्ते की कीमत पर नहीं है। स्पष्टतः, पुतिन मोदी की अमेरिकी समस्या को समझते हैं। वे जानते हैं कि भारत को अमेरिका संग एक व्यापार समझौता की जरूरत है। अगर भारत रूस के साथ अपने रिश्ते को लेकर अमेरिका की चिंता दूर कर दे, तो अगले साल ट्रंप को भारत आने के लिए भी लुभा सकता है। खासकर, अगर इस बीच यूक्रेन पर अमेरिका-रूस समझौता हो जाए तो।

इस निडर, नई मिश्रित दुनिया में, जहां बड़ी ताकतों की छाप बड़ी है, भारत जैसे देशों को मोलभाव करना, किनारे हटना, परे रहना और मध्यस्थता करना सीखना होगा। आज़ादी के बाद शुरुआती मुश्किल दिनों से भारत यही करता था, जब उसने उन ताकतों के आगे झुकने से मना किया, जो भारत को गठबंधन विशेष हेतु लुभा रहे थे। सभी पक्षों के साथ खेलने की यह काबिलियत – सिर्फ़ एक यानि अमेरिका से नहीं, जिससे भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना ज्यादा ही दिल लगा रखा है – भारत के लिए न केवल इसलिए कामगर है कि वह एक छोटी ताकत है, बल्कि एक प्राचीन देश है। इसमें जहां उच्च एवं नैतिक आधार का उपदेश देने की काबिलियत है वहीं साम, दाम, दंड, भेद बरतने की भी, राजकाज का आम तरीका, जिसमें मान-मनौव्वल के संग प्रलोभन, दंड और विभाजन भी शामिल है।

मोदी समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छवि बनानी है , तो अपनी आर्थिक ताकत दिखानी होगी। इसके लिए, पुराने वक्त में कभी दोस्त रहे, देंग शियाओ पिंग द्वारा दिए पूर्ण पूंजीवाद के नारे को दिल में रखना होगा और इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का केंद्रीय सिद्धांत बनाना होगा। उनका यह कथन भीः'जब तक बिल्ली चूहे पकड़ने लायक है, उसका रंग मायने नहीं रखता,'।

यह दौरा मोदी और पुतिन, दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसने रूसी राष्ट्रपति को दुनिया को यह संदेश देने लायक बनाया कि तमाम पश्चिमी पाबंदियों के बावजूद, रूस अलग-थलग नहीं है। उन्हें मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भारत दौरे से पुतिन ने अपने बढ़िया दोस्त, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को माओ के कथन 'सौ फूल खिलने दो' के जरिए यह संदेश दिया है कि बगीचे में और भी फूल खिले हुए हैं– यानि भारत।

अर्से बाद, अब ऐसा लगा कि भारत अपना वजूद दर्शा रहा है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का स्वागत एक पुराने दोस्त की भांति किया, लेकिन नज़र परिदृश्य में मौजूद दूसरे दोस्तों पर भी उतनी रखी। बहुध्रुवीय – या गुट-निरपेक्षता – का संदेश साफ़ है।

प्रेरणा

राजकवि का अप्रत्याशित वरदान

राजदरबार हमेशा की तरह भव्य था, लेकिन उस दिन उसमें एक अनोखी ऊर्जा तैर रही थी। स्वर्ण-मंडित स्तंभों पर दीपकों की लौ मनोहर छाया बना रही थी। सैनिक अपने स्थान पर स्थिर खड़े थे, दरबारी धीमी आवाज़ में आने वाली घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, और बीचोंबीच महा सिंहासन पर महाराज विराजमान थे—तेजस्वी, न्यायप्रिय और दूरदर्शी।

थोड़ी ही देर में दरबार का कक्ष अचानक शांत हो गया, क्योंकि सभा के द्वार पर राजकवि का प्रवेश हुआ—वह व्यक्ति जिसकी वाणी में ज्ञान की नदी बहती थी, और जिसके शब्दों में वर्षों का तप और अनुभूति समाहित होती थी। उनका आगमन किसी साधारण अतिथि का नहीं था; पूरा राज्य उनके विचारों को मार्गदर्शक की तरह मानता था।

राजा तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया।

"आचार्य, आपके आगमन से हमारा दरबार धन्य हो गया,"

राजा ने विनम्रता से कहा।

राजकवि ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया, और आशीर्वाद स्वर में कहा—

"महाराज, आपके शत्रु चिरंजीव हों।"

सभी दरबारी अवाक रह गए। क्षणभर को जैसे हवा भी थम गई।

राजा के चेहरे पर आश्चर्य से उठती भृकुटियाँ धीरे-धीरे क्रोध की लकीरों में बदलने लगीं।

वह भीतर ही भीतर जलने लगे— किसी शत्रु को चिरंजीव रहने की कामना कैसे उनके हित में हो सकती है? उन्होंने कठोर स्वर में कहा— "आचार्य, यह किस प्रकार की मंगलकामना है?

आपने मेरे शत्रुओं के दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया? क्या यह मेरे प्रति अनिष्ट की कामना नहीं है?"

राजकवि प्रथम दृष्टि में शांत थे, लेकिन उनकी आँखों में वह गहराई थी जो तूफ़ान को भी साध ले।

वे कुछ कदम आगे आए और अत्यंत शांत स्वर में बोले—

"महाराज, आपने मेरे शब्द सुने अवश्य, पर समझे नहीं।

मैंने आपको आशीर्वाद दिया है, पर आपने उसे ग्रहण नहीं किया।"

राजा का क्रोध अब भ्रम में बदल गया।

"कवि, स्पष्ट कहिए। मैं कैसे ऐसे आशीर्वाद को स्वीकार कर सकता हूँ जो मेरे विरोधियों का कल्याण करे?"

राजकवि ने अपने दंड को धरती पर हल्के से टिकाया और धीरे से बोले—

"राजन, इस संसार की सबसे बड़ी भूल मनुष्य तब करता है, जब वह समझ लेता है कि उसे अब किसी से भय नहीं।

प्रतिस्पर्धा, चुनौती और संघर्ष ही मनुष्य को शक्ति देते हैं।

शत्रु एक संकट मात्र नहीं, वह एक दर्पण है—जो हमें हमारी कमजोरियाँ दिखाता है, हमारी क्षमता जगाता है, और हमारे पराक्रम को जीवित रखता है।"

उन्होंने आगे कहा—

"सोचिए महाराज, यदि आपके शत्रु न रहें तो क्या होगा?

आपकी सेना ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि रक्षा का कोई भय नहीं रहेगा।

आपकी रणनीतियाँ कमजोर होने लगेंगी, क्योंकि अभ्यास और सावधानी समाप्त हो जाएगी।

आपकी बुद्धि में तीक्ष्णता कम आने लगेगी, क्योंकि चुनौतियाँ ही बुद्धि को धार देती हैं।

आप स्वयं उसी निश्चिंतता के आलस में डूब जाएंगे जिसे राजा का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है।"

दरबार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति राजकवि के शब्दों को गहराई से महसूस कर रहा था।

राजा विशेष रूप से स्तब्ध थे—मानो कोई उन्हें उनके भीतर का छिपा हुआ सत्य दिखा रहा हो।

राजकवि की आवाज़ अब और प्रभावशाली हो उठी—

"आपके शत्रु जीवित रहेंगे, तभी आपकी शक्ति जागृत रहेगी।

आपके निर्णय परिपक्व होंगे, आपकी रणनीतियाँ गहरी होंगी, और आपका राज्य सुरक्षित रहेगा।

मैंने आपके शत्रुओं का नहीं, आपका कल्याण सोचा है। आपका पराक्रम जीवित रहे, आपकी चेतना जागृत रहे—यह मेरी सच्ची मंगलकामना है।"

राजा अब स्थिर खड़े थे, और उनके नेत्रों में समझ का प्रकाश फैल चुका था।

उन्होंने धीरे-धीरे चलकर राजकवि के चरणों को स्पर्श किया और बोले—

"कवि, आज आपने मुझे वह सत्य बताया है जिसे जानने के लिए वर्षों की साधना चाहिए।

आप ठीक कहते हैं—शत्रु विनाश नहीं, हमारी शक्ति का प्रहरी है।

जो व्यक्ति चुनौतियों से रहित हो जाता है, वह स्वयं को खो देता है।"

पूरा दरबार राजकवि के ज्ञान से अभिभूत खड़ा था।

राजकवि ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा—

"महाराज, यही संसार की रीति है।

अंधकार न हो तो प्रकाश का मूल्य नहीं,

कठिनाइयाँ न हों तो सफलता का स्वाद नहीं,

और शत्रु न हों तो वीरता का अर्थ नहीं।"

उस दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह अब किसी भी विरोध, किसी भी संघर्ष, किसी भी चुनौती को वैर-भाव की दृष्टि से नहीं देखेंगे—

बल्कि उसे अपने सामर्थ्य का अनिवार्य साथी समझेंगे।

और इस प्रकार, राजकवि के अप्रत्याशित वरदान ने राजा को वह दृष्टि दे दी, जिसकी सहायता से वह आने वाले वर्षों में और भी महान शासक बना।

अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकते गांव, भारत की आर्थिक सूरत बदल रही

भारत ने 2024-25 में 35.77 करोड़ टन अनाज पैदा करके एक ऐतिहासिक रिकार्ड बनाया है। पिछले दस सालों में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 10 करोड़ टन बढ़ा है। यह खेती में आत्मनिर्भरता और गांवों के विकास की तरफ देश की लगातार बढ़ती रफ्तार को दिखाता है। इस समय जहां वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगभग तीन प्रतिशत है और जी-7 देशों की अर्थव्यवस्थाएं औसतन करीब 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, वहीं भारत में 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही है।

इन दिनों भारत के आर्थिक परिदृश्य से संबंधित विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में यह तथ्य रेखांकित हो रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ग्रामीण भारत से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इन रिपोर्टों के अनुसार गांवों में खपत तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण गरीबी में कमी, छोटे किसानों की साहूकारी कर्ज पर निर्भरता में कमी, ग्रामीण खपत में वृद्धि, किसानों का जीवन स्तर बढ़ने जैसी विभिन्न अनुकूलताओं से ग्रामीण भारत मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा की हालिया बैठक में कहा भी कि भारत में महंगाई घटने में कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी महंगाई नियंत्रण में खाद्यान्न उत्पादन की अहम भूमिका रहेगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सुधार, बेहतर कृषि उत्पादन, ग्रामीण उपभोग में बढ़ोतरी तथा कर सुधार जैसे घटकों के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसी तरह एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा प्रकाशित एशिया-पैसिफिक इकोनमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 के मुताबिक ग्रामीण भारत में विकास की सकारात्मकता है। महंगाई घटने और करों में कटौती से भारत की ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में 76.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में उपभोग वृद्धि और 39.6 प्रतिशत परिवारों में आय में वृद्धि सामने आई है। इसी तरह एसबीआइ रिसर्च द्वारा गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी में कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से आई है। जहां 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत और शहरी गरीबी 13.7 प्रतिशत थी, वहीं 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86 प्रतिशत और शहरी गरीबी घटकर 4.09 प्रतिशत पर आ गई है। हाल में जारी नाबार्ड की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अब 54.5 प्रतिशत परिवार औपचारिक स्रोतों-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों आदि से ऋण लेते हैं, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। उल्लेखनीय है कि 2019 से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भी करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मजबूती दे रही है। अप्रैल 2020 से शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण व्यवस्था ने अच्छी प्रगति की है। गांवों में बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2010 के 33,378 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 56,579 हो गई है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था भी प्रभावी भूमिका निभा रही है। सरकार ने बीते 11 वर्षों में फसलों पर दी जाने वाली सब्सिडी और फसल बीमा राशि को बढ़ाया है।

हालांकि देश का कुल कृषि निर्यात 50 अरब डालर के पार पहुंच गया है, लेकिन हमें अभी भी ग्रामीण भारत के विकास और किसानों की प्रगति के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। छोटे और सीमांत किसान आधुनिक खेती की तकनीक अपनाने में असमर्थता अनुभव कर रहे हैं। छोटे किसान आनलाइन खरीदारी में बहुत पीछे हैं। अभी भी ग्रामीण जनजीवन के करीब 22 प्रतिशत लोगों की कर्ज के लिए साहूकारों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता बनी हुई है। यह वर्ग ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता है और उसकी औसत ब्याज दरें लगभग 17-18 प्रतिशत से भी अधिक होती हैं।

जब छोटे किसानों को मौसमी जोखिम और सरकार से पर्याप्त धन हस्तांतरण की कमी का सामना करना पड़ता है, तब वे भारी ब्याज के बावजूद साहूकारों की चौखट पर दस्तक देते हैं। कई बार छोटे किसान औपचारिक स्रोतों से ऋण लेना तो चाहते हैं, मगर इसमें दस्तावेजों की कमी, गारंटी दाता का अभाव एवं अन्य शर्तें बाधा डालती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत कृषि परिवार अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में गांवों में साहूकारों और अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता घटाने के लिए बैंक शाखा विस्तार के अलावा अन्य कदम उठाने की भी जरूरत है। यह समय की मांग है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतिम छोर तक मजबूत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की भूमिका को प्रभावी बनाया जाए। गांवों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का तेजी से विस्तार करना होगा। इससे छोटे किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाई जा सकेगी। देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने की डगर पर भी आगे बढ़ना होगा।

अभियान

रामगंज बालाजी: वह दिव्य धाम जहां हनुमान स्वयं भक्त के हृदय की मौन पुकार सुन लेते हैं

राजस्थान की हाड़ौती धरती पर बसे बूंदी जिले के छोटे से कस्बे रामगंज का बालाजी धाम ऐसा स्थान है, मानो किसी प्राचीन युग का वह अध्याय जो आज भी सांस लेता है, चलता है और आस्था की लहरों में डूबा हुआ भक्तों को अपने भीतर खींच लेता है। कहते हैं कि दुनिया में भगवान के लाखों मंदिर हैं, लेकिन ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहां देवता भक्त की बोली हुई नहीं, बल्कि अनकही इच्छा को भी समझ लेते हों। रामगंज बालाजी वही अनोखी भूमि है, जहां हनुमान जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके सामने खड़े होते ही हृदय की वह कंपित भावना, वह छिपा हुआ दर्द, वह अधूरा सपना, सब बिना बोले उनके चरणों तक पहुंच जाता है।

यह बालाजी किसी साधारण मंदिर की प्रतिमा नहीं, बल्कि उस तेज का प्रतीक हैं, जो कभी सूर्य को भी अपने मुख में समा लेने वाला वीर था। हनुमान की यह मूर्ति जब सूरज की रोशनी में दमकती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं आराध्य राम का आदेश उनके भीतर जलता हुआ दीपक हो, जो हर भक्त पर अपनी प्रकाश ज्योति बरसाने को तत्पर है। बूंदी से आठ किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल यद्यपि आधी सदी पुराना बताया जाता है, पर इसके पत्थरों पर अंकित कला स्पष्ट बताती है कि यह हाड़ा राजपूत काल का स्थापत्य चमत्कार है। विशाल दरवाजा, बूंदी किले के झूला चौका की याद दिलाता हुआ, अपनी गंभीर खामोशी में सैकड़ों सालों की कथाएं समेटे प्रतीत होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन मिलता है शांत, सौम्य और दिव्य राम दरबार का—भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण। और ठीक सामने बैठे हैं बालाजी, जैसे वह पहरा दे रहे हों कि कोई भी भक्त राम के दर्शन से वंचित न रहे। दोनों प्रतिमाओं का यह आमना-सामना इतना अद्भुत है कि ऐसा लगता है जैसे राम अपनी कृपा का प्रवाह हनुमान को दे रहे हों और हनुमान उसे आगे भक्तों में वितरित कर रहे हों।

इस मंदिर की सबसे रहस्यमय और चमत्कारी विशेषता है—हनुमान जी के हाथ में रखा हुआ कमल का फूल। आमतौर पर हनुमान को गदा या पर्वत के साथ देखा जाता है, पर यहां कमल का यह एक फूल उनकी शक्ति को एक अलग ही अर्थ देता है। कमल, जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, जैसे कह रहा हो कि भक्त चाहे कितने भी संकट में क्यों न हो, उसकी आत्मा के भीतर स्वच्छ प्रकाश का एक फूल हमेशा जीवित रहता है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जीवन में कोई बड़ी बाधा आए, कोई काम अटक जाए या कोई भय मन को जकड़ ले—तो यहां कमल चढ़ाने मात्र से वह संकट गलने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पिघला दिया हो।

कमल की चर्चा होते ही उस पुरातन कथा का स्मरण हो आता है—जब भगवान राम पूजा के लिए 108 नीलकमल मांग रहे थे और एक कमल कम पड़ गया था। तब हनुमान जी ने अपने नेत्र को ही कमल मानकर राम के चरणों में रख दिया। वह भक्ति, जो शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की समर्पण में बदल जाती है, वही भावना इस धाम में हर पल बहती प्रतीत होती है।

कहते हैं रामगंज बालाजी धाम में कई चमत्कार घटते हैं। भक्त बताते हैं कि यहां आते ही मन का बोझ हल्का हो जाता है, हृदय की धड़कनें शांत हो जाती हैं और एक ऐसी दिव्य ऊर्जा शरीर में भर जाती है जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल है। यह वह स्थान है जहां लोग बिना बोले अपनी मुराद पूरी होते देख चुके हैं, जहां बालाजी केवल प्रतिमा नहीं, बल्कि जीवित उपस्थिति की तरह अनुभूत होते हैं। लोगों का कहना है कि बालाजी की स्वर्णाभा प्रतिमा को देखते ही अंदर एक तेज, एक हिम्मत, एक अद्भुत उत्साह जाग उठता है—जैसे कोई व्यक्ति अचानक भूल गया दर्द याद करते ही ठीक हो गया हो।

धाम तक पहुंचना भी सरल है। कोटा से सड़क, रेल और विमान—तीनों मार्ग इसे भक्तों के लिए सहज बनाते हैं। बूंदी के रास्ते में थोड़ी दूर निकलते ही यह स्थान दिख जाता है, और यहीं मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के ठहरने का भी प्रबंध किया है ताकि कोई भी श्रद्धालु अधूरी यात्रा लेकर न लौटे।

रामगंज का यह धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, एक अनुभव है—श्रद्धा का, समर्पण का, और उस मौन संवाद का जो भक्त और भगवान के बीच किसी भाषा का मोहताज नहीं। यहां भक्त केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि भीतर कुछ बदलकर जाता है। यहां हनुमान केवल सुनते नहीं, बल्कि हर धड़कन के पीछे छिपी पुकार को महसूस करते हैं। यही रामगंज बालाजी की सबसे बड़ी महिमा है—भक्ति यहां कही नहीं जाती, बस जी जाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

देशभर में फैले साइबर ठगी गिरोह का बड़ा भंडाफोड़, सोशल मीडिया पर 'निवेश गुरु' बनकर 6.33 करोड़ की ठगी, तीन गिरफ्तार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे देशव्यापी साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया पर खुद को 'निवेश गुरु' और सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर बताकर लोगों से करोड़ों रुपये ठग रहा था। पुलिस ने गिरोह के तीन मुख्य संचालकों को गिरफ्तार किया है और 6.33 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा किया है। गिरोह के खिलाफ अब तक 165 साइबर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह नेटवर्क काफी बड़े पैमाने पर सक्रिय था और देशभर में लोगों को निशाना बना रहा था।

पुलिस की जांच के मुताबिक यह गिरोह सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन, फर्जी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, नकली सेबी प्रमाणपत्र और बनावटी ट्रेडिंग ऐप दिखाकर लोगों को निवेश के भारी लाभ का लालच देता था। शुरुआत में पीड़ितों को हल्का सा मुनाफा दिखाकर उनका विश्वास जीता जाता था और फिर उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए उकसाया जाता था। जैसे ही पैसा उनके नेटवर्क में चला जाता, पीड़ितों को ब्लॉक कर दिया जाता या फर्जी तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाया जाता।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओडिशा निवासी प्रवेश चंद्र पांडा, प्रीतम रोशन पांडा और श्रीतम रोशन पांडा के रूप में हुई है। ये तीनों ओडिशा में फैले एक बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क को संचालित कर रहे थे, जिसके जरिए ठगी की भारी भरकम रकम को कई परतों में घुमाकर असली स्रोत और सरगनाओं तक पहुंचाया जाता था। इनके पास से 17 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड, 124 एटीएम/डेबिट कार्ड, दर्जनों पासबुक, चेक बुक और अन्य वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं।

इस गिरोह का भंडाफोड़ एक पीड़ित की शिकायत पर हुआ, जिसमें उसे भारी मुनाफे का भरोसा दिलाकर 49.73 लाख रुपये ठगे गए थे। जांच में पता चला कि यह रकम कई बिजनेस खातों के जरिये ओडिशा के म्यूल अकाउंट्स में भेजी गई थी और फिर धीरे धीरे एटीएम से निकालकर गिरोह के सरगनाओं तक पहुंचाई गई। पुलिस ने जब वित्तीय जांच को गहराई से खंगाला, तो पता चला कि इन खातों को केवल रकम के लेनदेन को छिपाने के लिए बनाया गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि प्रवेश चंद्र पांडा गंजम जिले में 'श्रीजी अपैरल्स' नामक म्यूल अकाउंट का मुख्य संचालक था। वही बैंक खातों, सिम कार्डों और डिजिटल लेनदेन चैनलों की व्यवस्था देखता था। उसके भतीजे प्रीतम और श्रीतम रोशन पांडा इस नेटवर्क को तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। उनके फोन और डिजिटल रिकॉर्ड में उन लेनदेन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जिनसे करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया था।

क्राइम ब्रांच के अनुसार यह गिरोह चार चरणों में काम करता था। पहले चरण में सोशल मीडिया पर निवेश सलाहकार बनकर लोगों को फंसाया जाता था। दूसरे चरण में शुरुआती रकम बिजनेस खातों में डालकर पीड़ितों का भरोसा जीता जाता। तीसरे चरण में रकम को अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में घुमाया जाता और चौथे चरण में नकदी निकालने वाली टीम एटीएम से पैसा निकालकर सरगनाओं को सौंप देती। यह बहु स्तरीय व्यवस्था इतनी जटिल थी कि आम व्यक्ति के लिए ठगी का पता लगाना almost असंभव हो जाता।

देशभर में तेजी से बढ़ रही साइबर ठगी को देखते हुए पुलिस इस केस को एक बड़ा ऑपरेशन मान रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरह के गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की वित्तीय जानकारी, उनकी रुचि और मनोविज्ञान का अध्ययन कर उन्हें निशाना बनाते हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और मुख्य सरगनाओं की तलाश में जुटी है, जिनके विदेश में होने की भी आशंका है।

क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि किसी भी 'स्टॉक गुरु', 'इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट', 'प्री IPO ऑफर' या 'अत्यधिक मुनाफा' देने वाले ऑनलाइन दावों से सावधान रहें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी निवेश से पहले प्रमाणित स्रोतों और आधिकारिक वेबसाइटों की ही जांच करें।

जूनियर एनटीआर की पहचान के अनधिकृत उपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को त्वरित कार्रवाई का निर्देश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। तेलुगु सुपरस्टार नंदमुरी तारक रामाराव जूनियर, जिन्हें आमतौर पर जूनियर एनटीआर के नाम से जाना जाता है, की पहचान, नाम और तस्वीर का बिना अनुमति उपयोग करने वाले मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स साइट्स को तीन दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह निर्देश तब दिया, जब जूनियर एनटीआर की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जूनियर एनटीआर की शिकायत को आईटी एक्ट के तहत औपचारिक शिकायत की तरह दर्ज किया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की

जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें विस्तृत आदेश जारी होने की संभावना है।

हाईकोर्ट हाल के दिनों में सेलिब्रिटी और सार्वजनिक हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय है। इससे पहले 27 नवंबर को अभिनेता अजय देवगन की पहचान से जुड़े कंटेंट के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। अदालत ने एआई और डीपफेक तकनीक से बनाए गए वीडियो और डिजिटल सामग्री को इंटरनेट से हटाने के निर्देश भी जारी किए थे।

इसके अलावा अदालत ने हाल के आदेशों में कई अन्य हस्तियों की पहचान के दुरुपयोग पर भी रोक लगाई है, जिनमें अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर, अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और निर्माता करण जौहर शामिल हैं। इन आदेशों का उद्देश्य डिजिटल युग में सेलिब्रिटी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके बिना अनुमति उपयोग को रोकना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनधिकृत कंटेंट तेजी से फैलता है और सेलिब्रिटीज़ की पहचान, प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो न केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाते हैं बल्कि आम उपयोगकर्ताओं को भी चेतावनी देते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान का दुरुपयोग गंभीर कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।

डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा और सेलिब्रिटी की पहचान के सुरक्षित उपयोग की दिशा में यह कदम न्यायालय की सक्रियता और कानून की सख्ती का स्पष्ट संदेश देता है। अदालत ने प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे जूनियर एनटीआर की पहचान से जुड़े सभी अनधिकृत कंटेंट को हटाने, प्रभावित सामग्री की पहचान करने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रभावी प्रणाली लागू करें।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदेश केवल जूनियर एनटीआर तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे उद्योग और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मिसाल कायम करता है। इस निर्णय से स्पष्ट संकेत जाता है कि सेलिब्रिटीज़ के व्यक्तित्व अधिकारों का सम्मान और डिजिटल कंटेंट के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करना अब कानूनी दायरे में सख्ती से पालन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पर कड़ी निगरानी: पांच नए स्पेशल ऑब्जर्वर तैनात, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास

(जीएनएस)। कोलकाता। आगामी चुनावों की तैयारी के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की निगरानी को और सख्त कर दिया है। राज्य में पहले से ही नियुक्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के बाद अब आयोग ने पांच डिवीजनों में नए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। यह कदम विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फॉर्म वितरण, संग्रह, डिजिटाइजेशन और ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले सभी गतिविधियों पर त्रुटिरहित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गलती, अनियमितता या लापरवाही को रोकने के लिए ईसीआई ने निरीक्षण व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। इससे यह संदेश भी जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, नए ऑब्जर्वरों की नियुक्ति से मतदाता सूची से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और आगामी चुनावों में किसी भी विवाद की संभावना कम होगी।

पांच डिवीजनों में नियुक्त नए ऑब्जर्वरों की सूची इस प्रकार है: प्रेसिडेंसी डिविजन (कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया) में रविकांत, मेदिनीपुर डिविजन (पश्चिम/पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया) में नीरज कुमार बनसोर, बर्दवान डिविजन (बीरभूम, पश्चिम/पूर्व बर्दवान, हुगली) में कृष्ण कुमार निराला, मालदा डिविजन (मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर/दक्षिण दिनाजपुर) में आलोक तिवारी और जलपाईगुड़ी डिविजन (दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर) में पंकज यादव। इन ऑब्जर्वरों का कार्य मतदाता सूची से जुड़ी सभी गतिविधियों का निरंतर निरीक्षण करना और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना होगा। इससे पहले सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता को एसआईआर की संपूर्ण व्यवस्था की समीक्षा और राज्य में विशेष निरीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था। अब डिवीजन स्तर पर नई तैनाती से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आयोग मतदाता सूची की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

राज्य के चुनाव अधिकारी भी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक उपाय समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। मतदाता सूची में सुधार और अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए डाटा संग्रह, फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने और चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की कड़ी निगरानी से मतदाता सूची में त्रुटियों की संभावना कम होगी और चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास मजबूत होगा। नए ऑब्जर्वरों की जिम्मेदारी केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वे स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी देंगे, ताकि सभी प्रक्रियाएं नियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप पूरी हों।

इस अभियान से न केवल मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि राज्य में चुनावी तैयारियों की गति भी बढ़ेगी। आयोग की यह पहल यह संदेश देती है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ेगी और यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

भावनगर रेलवे मंडल पर मनाया गया डॉ. भीमराव आंबेडकर जी का 70वाँ "महापरिनिर्वाण दिवस"

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल पर भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का 70वाँ महापरिनिर्वाण दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, जिसे प्रतिवर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

दिनांक 06 दिसंबर 2025 (शनिवार) को मंडल कार्यालय में प्रशासनिक अवकाश होने के कारण यह कार्यक्रम 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित मंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखकर उनकी स्मृति को नमन किया।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को स्मरण किया।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के विभिन्न ट्रेड यूनियनों, एससी/एसटी एसोसिएशन एवं ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में बाबा साहेब के विचारों, सामाजिक न्याय, समानता एवं संविधान के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करने तथा समाज में समता, बंधुत्व एवं न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: चार नेपाली नागरिकों के शव नेपाल भेजे जाएंगे

(जीएनएस)। काठमांडू। भारत के गोवा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में चार नेपाली नागरिकों की मौत हो गई है। नेपाल दूतावास नई दिल्ली, गोवा सरकार के समन्वय में मृतकों के शवों को नेपाल लाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से गोवा सरकार ने मृतकों की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सभी शव नेपाल भेज दिए जाएंगे। मृतकों में से दो की पहचान पहले ही चूर्ण बहादुर पुन और विवेक कटवाल, दोनों झापा जिले के निवासी, के रूप में हो चुकी है। शेष दो शवों की पहचान की प्रक्रिया और उनके घर का पता लगाने का काम अभी जारी है।

गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित इस नाइट क्लब में शनिवार मध्यरात्रि को लगी आग में कुल 25 लोगों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए राहत उपाय किए गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मृतकों के

परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

नेपाल दूतावास ने मृतकों के परिजनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है और उनके शवों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए गोवा प्रशासन के साथ समन्वय कर रहा है। राजदूत डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

इस घटना ने नाइट क्लब सुरक्षा और आपात प्रबंधन के महत्व को फिर से उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की जांच के बाद ही आग लगने के कारण और संभावित सुरक्षा चूक के पहलुओं का पता चल सकेगा। गोवा प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कड़े नियम और निगरानी बढ़ाई जाएगी।

अहमदाबाद मण्डल पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में आज मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा तथा अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. बी.आर.अम्बेडकर की छवि पर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्ज्वलित कर उन्हें नमन किया।

कार्यक्रम में मण्डल के रेल अधिकारी, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, ओबीसी एसोसिएशन, एससी/एसटी एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने उपस्थित होकर डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्पेशल खेल महाकुंभ में 'वोरियर' टीम का शानदार प्रदर्शन, लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल पर कब्जा

(जीएनएस)। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गुजरात सरकार की प्रेरणा से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विशेष खेल महाकुंभ में दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा ने एक बार फिर अपनी उड़ान भरी है। इसी कड़ी में श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल (कप्तान) के नेतृत्व में 'वोरियर' टीम ने पेरा सिटिंग वॉलीबॉल खेल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।

यह प्रतियोगिता दिनांक 07/12/2025 (रविवार) को सिदसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनडोर स्टेडियम, भावनगर में पेरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, भावनगर की अगुवाई में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भावनगर जिले की कुल 7 टीमों ने भाग लिया, जिन सभी को पराजित करते हुए 'वोरियर' टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि 'वोरियर' टीम ने यह खिताब लगातार तीसरी बार जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। यह उपलब्धि टीम की कड़ी मेहनत, अनुशासन और कप्तान श्री पराक्रमसिंह गोहिल के कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

दिव्यांग कर्मचारी श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल वर्तमान में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में वाणिज्यिक विभाग में मुख्य वाणिज्य क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। अब जनवरी 2026 में श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल की अगुवाई में 'वोरियर' टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने चैम्पियनशिप खिताब का बचाव (डिफेंड) करने हेतु नडियाद के लिए रवाना होगी। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुश्री नीलादेवी झाला एवं भावनगर मंडल के सभी शाखा अधिकारियों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य में उनकी शानदार उपलब्धियों की कामना की।

संयुक्त राष्ट्र के FAO और भारत की साझेदारी से देश में नेक्स्ट जेन 'स्मार्ट ब्लू रिवॉल्यूशन', गुजरात के जखाऊ में भी बनेगा विश्वस्तरीय ब्लू हार्बर मॉडल

- जखाऊ (गुजरात), वनकबारा (दमन-दीव) और कराईकल (पुडुचेरी) में विकसित होंगे विश्वस्तरीय ब्लू हार्बर मॉडल
- PMMSY के तहत 452.32 करोड़ रुपये की स्मार्ट फिशिंग अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू
- आगामी VGRC में कच्छ-सौराष्ट्र के तटीय विकास और ब्लू इकॉनमी पर रहेगा विशेष फोकस

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में उसका नेतृत्व सिर्फ दूरदर्शी ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और परिणाम-केंद्रित भी है। तेजी से बदलते समुद्री परिदृश्य में आज फिशिंग हार्बर सिर्फ संरचनात्मक सुविधाएँ नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, समुद्री आजीविका और तटीय समुदायों की समृद्धि के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। इसी दृष्टिकोण के केंद्र में है गुजरात द्वारा विकसित की जा रही "ब्लू हार्बर" अवधारणा, जो पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक दक्षता और सामाजिक समावेशन को एक साथ लेकर चलती है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी तटीय अवसंरचना को नई गति देने के प्रयास तेज हो गए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मत्स्य विभाग (DoF), मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ एक ऐतिहासिक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत जखाऊ (गुजरात), वनकबारा (दमन-दीव) और कराईकल (पुडुचेरी) में विश्व-स्तरीय "ब्लू हार्बर" स्थापित किए जाएंगे जो देश में स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी मत्स्य अवसंरचना के नए राष्ट्रीय मानक गढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 452.32 करोड़ रुपये के निवेश से स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएँ तटीय विकास को तेज़ी से बदल रही हैं। इन परियोजनाओं से न सिर्फ समुद्री मत्स्य व्यवसाय आधुनिक होगा बल्कि भारत के वैश्विक समुद्री-आहार बाजार में भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढ़ेगा।

कच्छ जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित जखाऊ हार्बर गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मत्स्य केंद्रों में से एक है और यह राज्य की ब्लू ग्रोथ विज़न का प्रमुख आधार भी बना हुआ है। मत्स्य आयुक्त (COF) द्वारा प्रबंधित यह हार्बर हजारों मत्स्य-जीवियों के जीवन का केंद्र है और समुद्री सुरक्षा दृष्टि से भी अत्यंत रणनीतिक है। जेटी, मरम्मत क्षेत्र, भंडारण प्रणालियों और कटाई-परवर्ती सुविधाओं से लैस जखाऊ को हाल ही में "ब्लू रिवॉल्यूशन" पहल में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य इसकी अवसंरचनात्मक क्षमता को आधुनिक वैश्विक मानकों तक ले जाना है।

इसी पृष्ठभूमि में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में राजकोट में आयोजित होने जा रही है। कच्छ और सौराष्ट्र जो अपने समृद्ध मत्स्य संसाधनों, महत्वपूर्ण समुद्री हार्बर्स और मजबूत तटीय अवसंरचना के लिए देशभर में प्रसिद्ध है, पर इस बार विशेष फोकस रहेगा । यह क्षेत्र न सिर्फ समुद्री मत्स्य क्षेत्र के गतिविधियों और वैल्यू-चेन लॉजिस्टिक्स के प्रमुख द्वार हैं बल्कि भारत की उभरती ब्लू इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण इंजन बन रहे हैं। सम्मेलन में नीति-निर्माताओं से लेकर उद्योग जगत के नेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों तक सभी एक मंच पर आएंगे जिसका उद्देश्य नए निवेश अवसरों, नवाचारों, उभरती तकनीकों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक साझा दृष्टि विकसित करना।

राजकोट में अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित किसानों से किया संवाद, भाजपा के दमन के खिलाफ आवाज बुलंद

(जीएनएस)। राजकोट। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को गुजरात के राजकोट में पीड़ित किसान परिवारों से मिले और उनके संघर्ष का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दमन से पूरा गुजरात त्रस्त है, लेकिन इस बार राज्य की जनता का गुमान टूटने वाला है। किसान परिवारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने जेल से बाहर आए किसानों को सम्मानित किया और उनके साथ संवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने मिलकर देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन आज गुजरात में किसानों को उनके हक के लिए आंदोलन करने पर दमन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले महीने हड़दड़ आंदोलन के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल में डाला गया। केजरीवाल ने बताया कि जब वे खुद किसानों से मिलने गुजरात आए, तो भाजपा सरकार ने पुलिस के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश की और सभा का मंच तोड़वा दिया। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी तब तक चैन की सांस नहीं लेगी जब तक जेल में बंद सभी किसान बाहर नहीं आ जाते। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना पर्याप्त नहीं है, न्याय पाने के लिए जनता को मतदान के माध्यम से सत्ता बदलनी होगी। हड़दड़ आंदोलन में 88 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया था। अब तक 42 किसान जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन 46 लोग अभी भी जेल में हैं। पार्टी ने वकीलों की टीम बनाई है जो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने में सक्रिय है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात के कोने-कोने में शराब और ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, लेकिन सरकार इन अपराधों पर कार्रवाई नहीं कर रही। केवल किसानों को दबाया जा रहा है, जबकि असली अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने अहंकार और सत्ता के दमन से किसानों को निशाना बना रही है, लेकिन इस बार जनता का यह गुमान टूटने वाला है। AAP के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि हड़दड़ क्रांति ने राज्य में नई हिम्मत और आजादी की भावना पैदा की है। पिछले 30 वर्षों से जनता दमन सह रही थी, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने बताया कि सुदामड़ा, जामनगर, खंभालिया, सोमनाथ, बारडोली, आनंद, बनासकांठा में हजारों किसान एकत्र हो चुके हैं और 14 दिसंबर को कच्छ में किसान महापंचायत आयोजित होने जा रही है। राय ने कहा कि यह क्रांति केवल किसानों के संघर्ष की वजह से शुरू हुई है और अब इसे रोक पाना नामुमकिन है। केजरीवाल ने किसानों से अपील की कि वे अपने हक की लड़ाई जारी रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा को गुजरात से भगाने के लिए लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उनके अनुसार, हड़दड़ आंदोलन केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरे गुजरात के किसानों की आवाज है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और उनके हक के लिए कानूनी और राजनीतिक संघर्ष दोनों जारी रहेगा। राजकोट में हुई यह बैठक न केवल पीड़ित किसानों के लिए सहारा बनी, बल्कि पूरे राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध की ज्वाला को और भड़का रही है। किसान महापंचायत और आगामी आंदोलन यह दर्शाते हैं कि गुजरात में सत्ता और किसान आंदोलन के बीच टकराव और तेज होने वाला है।

रिलायंस समूह की बड़ी पहल: भारत में अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संयंत्र, देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिलेगा नया बल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत में अत्याधुनिक और पूर्णतः एकीकृत सौर ऊर्जा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह संयंत्र इनगॉट, वेफर, सेल और मॉड्यूल निर्माण—सौर ऊर्जा उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया—को एक ही छत के नीचे लाएगा, जिससे न केवल उत्पादन प्रक्रिया में दक्षता बढ़ेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि यह परियोजना नई तकनीकों और उन्नत उत्पादन क्षमताओं से लैस होगी। कंपनी ने कहा कि भारत को 2030 तक प्रतिवर्ष 55–60 गीगावाट सौर मॉड्यूल की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान घरेलू उत्पादन क्षमता इस मांग का केवल लगभग 10 प्रतिशत ही पूरा कर पाती है। ऐसे में रिलायंस का यह संयंत्र देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की बढ़ती मांग और घरेलू क्षमता के बीच की खाई को पाटने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

इस परियोजना के तहत स्थापित होने वाले संयंत्र में हाइब्रिड प्रौद्योगिकी और 24×7 सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाली नई तकनीकियों का उपयोग किया जाएगा। रिलायंस एनयू एनर्जीज, जो रिलायंस पावर की सहयोगी कंपनी है, साधारण सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर हाइब्रिड और स्टेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य न केवल स्थिर और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरे देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना भी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में स्थिर ऊर्जा भंडारण की वर्तमान क्षमता एक गीगावाट से भी कम है। रिलायंस की योजना के अनुसार, 2032 तक इसे 250 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में इजाफा होगा, बल्कि सौर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन के अवसर भी व्यापक होंगे। यह कदम भारत को वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

रिलायंस समूह के अधिकारियों ने बताया कि संयंत्र की स्थापना से रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के लिए यह क्षेत्र नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, यह परियोजना 'मेक इन इंडिया' पहल को सशक्त करेगी और भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक मानकों के अनुरूप क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। रिलायंस का यह कदम केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह देश की ऊर्जा रणनीति को भविष्य के लिए तैयार करने का एक प्रमुख प्रयास भी है। बढ़ती ऊर्जा मांग, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए यह परियोजना न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में रिलायंस का यह संयंत्र घरेलू और वैश्विक बाजार में भारतीय सौर ऊर्जा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूती देगा। यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे देश को विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। यह न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में भी लंबे समय तक स्थायी योगदान देगा। रिलायंस समूह की यह पहल देश को 2030 और उससे आगे के लिए स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

इंडिगो के बड़े संचालन संकट के बीच एयर इंडिया ने दिखाई मानवीयता, सीईओ ने कर्मचारियों से कहा-यात्रियों की मदद हमारी पहली प्राथमिकता"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों इतिहास के सबसे गंभीर संचालन संकट का सामना कर रही है। लगातार सातवें दिन भी उड़ानों में बड़े पैमाने पर व्यवधान देखने को मिला, जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं और कई लोग अपनी जरूरी यात्रा से वंचित रह गए। इस गंभीर स्थिति के बीच एयर इंडिया ने एविएशन उद्योग और देशवासियों के लिए एक मिसाल पेश की है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों से कहा कि वे इंडिगो के प्रभावित यात्रियों को भी उसी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ मदद करें जैसी वे अपने यात्रियों के लिए करते हैं।

विल्सन ने अपने कर्मचारियों को भेजे संदेश में बताया कि पिछले कुछ दिनों में एयर इंडिया का ग्राउंड स्टाफ और क्रू असाधारण व्यस्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में कर्मचारियों ने यात्रियों की हरसंभव सहायता की, चाहे वे एयर इंडिया के यात्री हों या किसी अन्य एयरलाइन के। "हमारी यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है—यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना। चाहे वे हमारे प्रतिद्वंदी हों या साझेदार, सहयोग और संवेदनशीलता हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए," उन्होंने कहा।

विल्सन ने संदेश में यह भी जोर दिया कि संकट की इस घड़ी में एयर इंडिया का स्टाफ न केवल अपने यात्रियों, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर के यात्रियों के लिए मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कई प्रेरक उदाहरण साझा किए, जिसमें एयर इंडिया की टीम ने इंडिगो के फंसे हुए यात्रियों को सहायता प्रदान की और उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद की। यह कदम इंडस्ट्री में एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है कि संकट की घड़ी में प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर मानवता और सहानुभूति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इंडिगो का संचालन संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले सात दिनों में लगभग 5,000 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। सोमवार को ही 400 से अधिक फ्लाइट कैंसिल की गईं। इसके कारण न केवल हजारों यात्री परेशान हुए, बल्कि हवाई अड्डों पर भी अव्यवस्था पैदा हो गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और संकेत दिया है कि इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह मामला केवल संचालन में व्यवधान का नहीं है, बल्कि यह यात्रियों के अधिकार और उनकी सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो का यह संकट पूरे एविएशन सेक्टर को प्रभावित कर रहा है। कई एयरलाइंस के स्टाफ और हवाई अड्डों की टीम को यात्रियों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में एयर इंडिया द्वारा उठाया गया कदम पूरे उद्योग के लिए एक मिसाल है। यह दिखाता है कि संकट की स्थिति में केवल व्यावसायिक लाभ या प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने के बजाय मानवीयता और सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

एयर इंडिया की पहल ने न केवल फंसे हुए यात्रियों को राहत दी, बल्कि पूरे उद्योग को यह संदेश दिया कि किसी भी एयरलाइन का मूल उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि संकट के समय में अन्य एयरलाइंस और उनके स्टाफ को भी इसी प्रकार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एयर इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे प्रतियोगिता कितनी भी कठोर हो, यात्रियों की सेवा और उनके प्रति संवेदनशीलता कभी पीछे नहीं रह सकती।

विल्सन ने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग और धैर्य बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का समर्पण और तत्परता ही एयर इंडिया की सफलता और विश्वसनीयता का आधार है। उन्होंने यह भी बताया कि एयर इंडिया की टीम ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए, जहां यात्रियों को तुरंत सहायता प्रदान की गई और उन्हें सुरक्षित ढंग से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।

इस संकट में एयर इंडिया की मानवीय पहल न केवल इंडस्ट्री में एक सकारात्मक संदेश फैलाती है, बल्कि यात्रियों और आम जनता में भी एयर इंडिया के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ाती है। यह कदम दिखाता है कि संकट की घड़ी में प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर मानवता, सहयोग और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय एयर इंडिया का यह कदम पूरे उद्योग के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। यह दिखाता है कि संकट की स्थिति में प्रत्येक एयरलाइन को अपने कर्मचारियों के माध्यम से मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और यही वह संदेश है जो एयर इंडिया ने इस संकट के समय में पूरे देश और एविएशन सेक्टर को दिया है।

इस तरह, इंडिगो के संचालन संकट के बीच एयर इंडिया ने साबित कर दिया कि यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य—यात्रियों की सेवा और सुरक्षा—सभी एयरलाइंस के लिए एक ही है। एयर इंडिया का यह कदम आने वाले समय में अन्य एयरलाइंस और पूरे एविएशन उद्योग के लिए एक प्रेरक मिसाल बन सकता है।

बीएपीएस प्रमुख स्वामी महाराज ने नर में नारायण देखने का वैदिक सिद्धांत साकार किया: अमित शाह

(जीएनएस)। अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को साबरमती रिवरफ्रंट पर बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव में अपने संबोधन में कहा कि बीएपीएस के प्रमुख स्वामी महाराज ने भक्ति और सेवा को जोड़कर वैदिक दर्शन को जीवंत रूप दिया और 'नर में नारायण' देखने के प्राचीन सिद्धांत को साकार किया। शाह ने अपने संबोधन में बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज ने आध्यात्मिकता और वैष्णव दर्शन को न केवल व्यापक बनाया, बल्कि इसे जीवन के व्यावहारिक पक्षों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, "प्रमुख स्वामी महाराज ने भक्ति और सेवा को जोड़कर नर में नारायण के वैदिक सिद्धांत को जीवंत किया। कर्म और करुणा के माध्यम से उन्होंने दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की प्राचीन ऋषि संस्कृति को पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही उन्होंने संपूर्ण सनातन धर्म के लिए महान कार्य किए। बिना किसी विशिष्ट शिक्षा दिए, उन्होंने सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों में संतत्व का सार स्थापित किया।"

तीन दिवसीय कार्यक्रम 2025 में प्रमुख स्वामी महाराज की बीएपीएस अध्यक्ष के रूप में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शाह के अलावा बीएपीएस प्रमुख महंत स्वामी महाराज और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में स्वामी महाराज द्वारा स्थापित सेवा एवं भक्ति के सिद्धांतों पर जोर दिया गया और उनके नेतृत्व में बीएपीएस संस्था के योगदान का विस्तार से उल्लेख किया गया। अमित शाह ने कहा कि बीएपीएस प्रमुख स्वामी महाराज ने न केवल आध्यात्मिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाया, बल्कि समाज में सेवा, करुणा और नैतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी महाराज की शिक्षाओं ने समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रेरित किया है और उनके प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। शाह ने समारोह में उपस्थित लोगों से स्वामी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करने और समाज में सेवा और करुणा के मूल्य बनाए रखने का आह्वान भी किया। बीएपीएस द्वारा आयोजित यह अमृत महोत्सव कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें समाज सेवा, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक प्रस्तुति और धार्मिक अनुशासन पर विभिन्न सत्रों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व और उनके योगदान को याद करने का अवसर है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित आदर्शों और सेवा की प्रेरणा को नए सिरे से मान्यता देने का भी अवसर प्रदान करता है।

समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्वामी महाराज की शिक्षाओं और उनके समाज में योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम ने स्पष्ट किया कि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के प्रयास और प्रमुख स्वामी महाराज की दूरदर्शिता से आध्यात्मिकता और सेवा का समन्वय समाज के लिए एक मार्गदर्शन बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शन के 'सुप्रभातम्' कार्यक्रम की सराहना की, योग और भारतीय जीवन शैली को बताया प्रेरणादायक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम 'सुप्रभातम्' की सराहना करते हुए इसे सुबह की ताजगी भरी शुरुआत का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल योग और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि भारतीय जीवन शैली, संस्कृति और परंपराओं के विविध पहलुओं को भी उजागर करता है। मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर साझा पोस्ट में कहा, "सुप्रभातम् कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से संस्कृत सुभाषितों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत के मूल्यों को नयी चेतना और प्रेरणा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अनूठा मिश्रण प्रदान करता है।'' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रभातम् कार्यक्रम ने भारतीय जीवन शैली, योग और स्वास्थ्य के महत्व को आम जनता तक सरल और आकर्षक ढंग से पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने यह बात उजागर की कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल नागरिकों को प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें दिनभर सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करते हैं। सुप्रभातम् के माध्यम से दर्शकों को रोजाना एक सुभाषित, योग से जुड़े अभ्यास, मानसिक स्वास्थ्य के सुझाव और जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण से परिचित कराया जाता है। मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय मूल्यों और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नई पीढ़ी को भी अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर दूरदर्शन के समस्त कर्मचारियों और कार्यक्रम से जुड़े आयोजकों की भी सराहना की, जिन्होंने नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट के माध्यम से जनता के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनाए रखा। उनके अनुसार, ऐसे कार्यक्रम न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। सुप्रभातम् कार्यक्रम देशभर में टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित होता है और लाखों दर्शकों को रोजाना सुबह स्फूर्ति, स्वास्थ्य और संस्कृति की ओर आकर्षित करता है। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना से यह कार्यक्रम और भी अधिक प्रतिष्ठा और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करेगा, साथ ही भारतीय परंपराओं और योग के महत्व को भी उजागर करेगा।

नोएडा में अंगीठी जलाने से सुरक्षा गार्ड की मौत, साथी की हालत गंभीर

(जीएनएस)। नोएडा। सेक्टर 48 में बीती रात एक दुखद घटना में दो सुरक्षा गार्ड अंगीठी जलाकर अपने गार्ड रूम में बैठे हुए जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज नोएडा के ईएसआईसी अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, धीरेंद्र कुमार और दिनेश कुमार (42) नामक गार्ड रात के समय कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोहे के तसले में आग जलाई और बंद कमरे में बैठे रहे। लोहे की अंगीठी से निकलने वाला धुआँ कमरे में जमकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। इससे दोनों गार्ड बेहोश हो गए और सांस लेने में असमर्थ हो गए। सुबह जब महिला सुरक्षा गार्ड प्रभा कुमारी ड्यूटी पर आई, तो उन्होंने दोनों को बेहोशी की हालत में पाया और तुरंत सिक्योरिटी कंपनी को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने दोनों गार्डों को नोएडा के सेक्टर 24 स्थित ईएसआईसी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने धीरेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि दिनेश कुमार का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

थाना सेक्टर 49 के प्रभारी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि यह हादसा अंगीठी जलाने के कारण उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हुआ। पुलिस ने घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिजन भी मौके पर मौजूद हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाना अत्यंत खतरनाक है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बन सकती हैं, जो तुरंत चेतनशीलता खोने और गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बनती हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने सभी गार्डों और कर्मचारियों को आग और अंगीठी का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। घटना ने यह भी उजागर किया है कि सर्दियों के मौसम में सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित हीटिंग और वेंटिलेशन की सुविधाओं की कमी कितनी घातक हो सकती है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कंपनियों को इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस ने मामले की संपूर्ण जांच के आदेश दिए हैं और आगामी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। वहीं मृतक के परिवार को इंसाफ और मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह दुखद हादसा नोएडा में सुरक्षा कर्मियों के लिए चेतावनी बन गया है कि सर्दी से बचने के लिए असुरक्षित तरीके अपनाना जानलेवा साबित हो सकता है।

दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और मानसिक शक्ति फ़ाउंडेशन ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित किया गहन सेमिनार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी (DTU) ने मानसिक शक्ति फ़ाउंडेशन के सहयोग से "छात्र मानसिक स्वास्थ्य" विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश के अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा विशेषज्ञों ने भाग लेकर छात्रों द्वारा सामना की जा रही मानसिक चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम की शुरुआत DTU के रजिस्ट्रार डॉ. संजीव राय ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए की और सेमिनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ छात्रों की मानसिक और भावनात्मक भलाई पर ध्यान देना आज के शैक्षणिक माहौल में अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात् मानसिक शक्ति फ़ाउंडेशन के निदेशक डॉ. अमरेश श्रीवास्तव ने मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य समर्थन तंत्र को सुदृढ़ करने और इसके लिए सभी हितधारकों—शिक्षक, परिवार और संस्थानों—द्वारा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया।

सेमिनार में दिनभर चलने वाले विभिन्न सत्रों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। डॉ. अमरेश श्रीवास्तव ने मानसिक कल्याण और वेलनेस पर अपने अनुभव साझा किए। प्रो. पंकज कुमार, प्रोफेसर ऑफ साइकैट्री, AIIMS पटना ने शारीरिक व्यायाम और पोषण के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया। प्रो. संजय गुप्ता, डीन, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने तनाव प्रबंधन की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की।

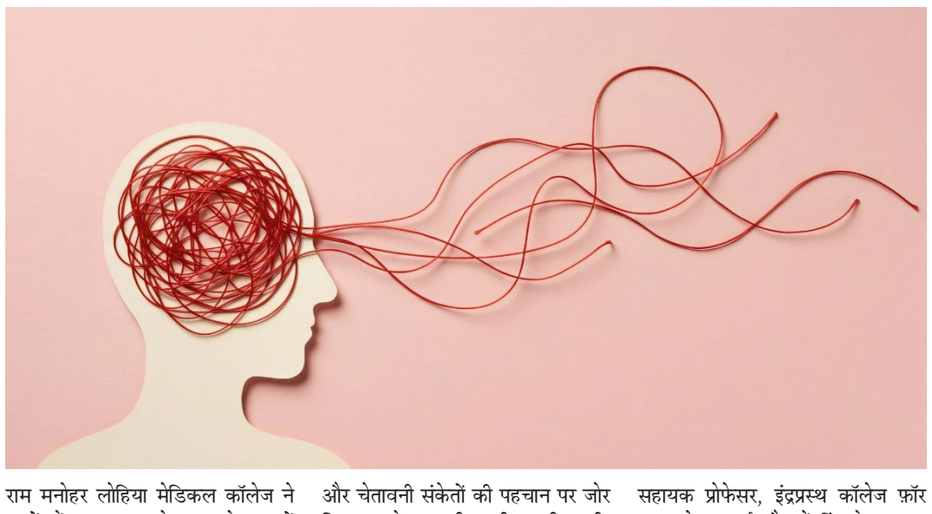

प्रो. मीना चंद्रा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज ने छात्रों में आत्महत्या रोकथाम के उपायों और चेतावनी संकेतों की पहचान पर जोर दिया। इसके साथ ही, सुश्री पावनी त्यागी, सहायक प्रोफेसर, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फ़ॉर वुमन ने परामर्श और मेंटरिंग के माध्यम से आत्महत्या रोकने की रणनीतियों पर अपने अनुभव साझा किए। डॉ. कुंवर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, अयोध्या मेडिकल कॉलेज ने शैक्षणिक चुनौतियों और छात्रों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के तरीकों पर प्रकाश डाला। प्रो. मनुश्री गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ साइकैट्री, सफदरजंग अस्पताल ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य के व्यापक पहलुओं पर चर्चा करते हुए जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।

कार्यक्रम का समापन मानसिक शक्ति फ़ाउंडेशन के रिसर्च एसोसिएट डॉ. गोविंद उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया, जिसमें उन्होंने सभी वक्ताओं, प्रतिभागियों और आयोजकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेमिनार संवाद, ज्ञान-विनिमय और सामूहिक प्रयास का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी ने इस सेमिनार के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समर्थन तंत्र को अपने शैक्षणिक ढांचे में शामिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्वविद्यालय ने कहा कि यह पहल छात्रों की मानसिक और भावनात्मक भलाई को बढ़ावा देने, तनाव कम करने और शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद करेगी।

विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए संस्थानों, शिक्षक और परिवारों को मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें छात्र अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में खुलकर बात कर सकें और समय पर सहायता प्राप्त कर सकें।

सेमिनार ने यह स्पष्ट किया कि छात्र मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक सामूहिक चुनौती है, जिसे केवल शैक्षणिक संस्थान ही नहीं, बल्कि समाज के हर हिस्से को मिलकर हल करने की जरूरत है। इस पहल के माध्यम से DTU और मानसिक शक्ति फ़ाउंडेशन ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सतत ध्यान देने और जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस प्रकार का एक दिवसीय सेमिनार न केवल ज्ञानवर्धन का अवसर प्रदान करता है, बल्कि छात्रों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य पर सहयोग और संवाद की संस्कृति स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यह कार्यक्रम भविष्य में ऐसे और पहलुओं और समाधानात्मक दृष्टिकोणों को शामिल कर छात्रों के लिए एक स्थायी लाभकारी मंच बन सकता है।